MOTION *RE*: NINETEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*Contd.*

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं यह जिक्र कर रहा था कि जिन सुविधाओं पर हम विचार कर रहे हैं उन में से एक घर की समस्या है। यह समस्या बहुत भयानक है विशेषत. उन लोगो के लिये जो आर्थिक दृष्टि से बिछडे हुए वर्ग के है, चाहे वे अनुसूचित जनजाति मे सम्मिलित हो चाहें अनुसूचित जाति में सम्मिलित हो। अपने देश मे प्राकृतिक साधन सम्पत्ति प्रचुर होने के बावजूद उस का उपयोग क्यो नही होता यह मेरी समझ मे नही आता। हम जो पाचवी पंच-वर्षीय योजना लाने जा रहे है उस मे कम से कम यह आश्वासन जरूर मिलना चाहिये कि हर गाव मे पेय जल की व्यवस्था होगी और किसी को भी चाहे वह पिछडे वर्ग का हो या जागृत वर्ग का हो, पेय जल की तकलीफ नही उठानी पडेगी। साथ ही कम से कम अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन-जातियो के लोगो को घर की समस्या का सामना नही करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी अगर हम उन के लिये कुछ कर पाये तो मैं समझूगा कि कम से कम कुछ मात्रा में तो कर पाये।

जब हम अनुसूचित जातियो की समस्याओं के ऊपर आते है तो उस के साथ एक पुरानी बीमारी लगी हुई दिखाई पड़ती है, जिस को हम एक कलंक ही कह सकते हैं, और वह है अस्पृश्यता, जो अनधासियो और जन-जातियों के अन्दर नहीं है। उस को निकालने की कोशिश बहुत पुराने जमानेसे होती चली आ रही है। बुद्ध भगवान के दिनों में अस्पृश्यता नाम की चीज नही थी। गीता में भी उस का कोई जिक्र नही किया गया है। गीता में सिर्फ चार वर्णों का जिक्र किया गया है। यह बीच में कैसे पैदा हो गई इस परिवर्तन का बाबा साहब अम्बेडकर भी पता नही लगा सके कि क्या खास कारण हो गया। कभी कभी गलत रुढ़िया समाज के अन्दर आ जाती है। तब शास्त्रो को भी कहना पड़ता है कि शास्त्रार्थ रुढ़िबलीयसी। कभी कभी उस को तोड़ना पड़ता है। हम लोग जो नियम मे बन्धे हुए है, नियम से इतने जकड़ जाते हैं कि उस के कारण जो जानकारी हम को चाहिये वह भी नही मिल पाती। जो कुर्सी पर बैठे हैं वह कहते है कि हम कुछ नही कर सकते क्योंकि हम नियम से बंधे हुए हैं। नियम जो होते है वह व्यवस्था के लिये होते है न कि किसी को रोकने के लिए। इस दृष्टि मे जो भी रूढ़ियां गलत तरीके से आ गई है उन को हटाने के लिये प्रयत्न करना पडता है। बसवेश्वर महाराज ने बारहवी शताब्दी में प्रयत्न किया, रामानुजाचार्य ने प्रयत्न किया, और आज जब नजदीक आते हैं तो दयानन्द महार्षि, महात्मा गांधी, वीर सावरकर और डा० हैडगवार आदि कितने लोगों ने प्रयास किया। किन्तु इतना होने के बाद भी हम इस कलंक से बच नहीं पाये। अलग अलग पन्थ निकलने के बाद भी लिंगायत पन्थ निकला, वीर शैव वालों ने 65 जातियों को बुला कर सब

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

के गले में लिंग बांध कर कह दिया कि कोई भेद भाव नहीं है आपस में, सब एक साथ हैं, किन्तु इतना होने के बाद भी उन में बेटी का व्यवहार नही । जैनियों का जो पन्थ निकला वह भी वैसे ही बैठा हुआ है, उसका भी वही हाल हुआ । सिखों का भी वही हाल हुआ, मजहबी सिख के नाम से वह मौजूद हैं । इसी तरह से ईसाई बने । मैं जानता हूं कि गोआ में जो ईसाई हैं वह भी आपस में जानते है कि यह ब्राह्मण ईसाई है और वह क्षत्रिय ईसाई है । वह एक दूसरे के साथ बेटी का व्यवहार नहीं करते ।

मैं समझता हू कि हम को समाज को समानता के आधार पर खडा करने की दृष्टि से आगे चलना होगा । मुझे इस बात का दुख है 25 साल की आजादी के बाद, महात्मा गांधी जी के बड़े भारी प्रयास करने के बाद भी, ज्यादा कुछ नही हो पाया है । मै इस सम्बन्ध मे किसी पार्टी को दोष नही देता हू । दोष सब का है । जो जन-जागरण होना चाहिये था वह हम लोगो ने नही किया । हम अपनी ही धुन में रह गये । हाथ मे अधिकार आने के बाद हम को लगा कि परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन आया ही नहीं । मैं जानता हू कि जहा मन्दिर प्रवेश का सवाल है, अच्छे अच्छे लोगों ने, यहां तक कि शिक्षकों ने भी कहना शुरू किया कि हम हिन्दू नहीं हैं और मन्दिर प्रवेश नही देंगे, जैनियों ने कहना शुरू किया कि हम हिन्दू नहीं हैं ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम को समानता के आधार पर समाज को खड़ा करना है तो जब तक हम देश में जन-जागरण नहीं करेंगे, सामाजिक क्रान्ति लाने की कोशिश नही करेंगे तब तक हमें लगता है कि यह कलंक मिटेगा नहीं । एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि जो समाज गाय को पवित्र मानता है, जो समाज कुत्ते को दत्तात्रेय की मूर्त्ति के पास रख कर उस को पवित्र समझता है वह किसी व्यक्ति को अपवित्र कैसे मान सकता है । यह बिल्कुल गलत रूढ़ि है । इस रूढ़ि की दीवार को हम को तोड़ना चाहिये, फोड़ना चाहिये । पच्चीस साल के अन्दर हम ने कुछ नही किया, इस को भूलना नहीं चाहिये । आज भी गाव गाव से हरिजन बड़ी अलग और गिरी हुई स्थिति मे हैं । उन के साथ दुर्व्यवहार होता है ? पीने का पानी नही मिलता, उन को खाना मिलना मुश्किल है । पढ़े लिखे लोगो को आज भी अच्छे अच्छे मोहल्लो मे मकान नही मिलता है । मै चाहता हू कि यह सब कानून बनाने से दूर नही हो सकता । जब तक हम मन में परिवर्तन नही करते, जब तक यह जो बड़ी भारी समस्या है उस की बीमारी मन में बैठी हुई है तब तक कुछ नहीं हो सकता है । आज आदमी को इलाज करने वाला डाक्टर बड़ा है और वेटरिनरी डाक्टर छोटा है, आदमी का बाल काटने वाला बारबार है और भैंस के बाल काटने वाला नाई छोटा है । यह हमारे मन में बैठा है । कोई भी काम समाज के लिए मैं करता हूं वह पवित्र

है, जब तक यह भावना समाज में जागृत नहीं होती है तब तक यह इसी तरह से चलता रहेगा । इसको जागृत करने के लिये शासन को कदम उठाने चाहिये थे । शिक्षा के माध्यम से जन-जागरण होना चाहिये था । समाजिक क्रान्ति शासन को लानी चाहिये थी । जो मन में परिवर्तन लाना चाहिये था उसको वह नहीं ला पाया है । आखिर हम सब परमात्मा के पुत्र होने के नाते एक ही स्तर पर एकता के आधार पर खड़े हैं । सब का सर्वांगीण विकास होना चाहिये । मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा का समग्र जीवन का विकास होना चाहिये । धर्म चक्र प्रवर्तनाय का यही मतलब है । यह शासन की जिम्मेदारी है । आर्थिक पिछड़ापन दूर करने की आवश्यकता थी । नौकरियां इनको देने की आवश्यकता थी । प्रारम्भिक शिक्षा भी मुफ्त हम नहीं दे पाते । आज भी उनके घरों में जा कर उनके बच्चों को नहीं लाया जाता है शिक्षा देने के लिए । बनवासी पहाड़ों में बिखरे पड़े हैं । उनके बच्चे कहां जाते हैं शिक्षा पाने के लिए । उनको शिक्षा कौन देगा ? जो पढ़ा लिखा है उसको यह कह कर नौकरी नहीं दी जाती है कि वह सूटेबल नहीं है । उसको नौकरी से इस आधार पर वंचित रखा जाता है । कई बार माननीय सदस्यों ने इस सवाल को यहां उठाया है । आज भी हम देखते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में इन जातियों के इनेगिने लोग ही हैं । आगे जैसे हम जाते हैं तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में तो पता चलता है कि कुछ नौकरियां उनको मिली हैं । यह जो भेद-भाव है यह कांग्रेस के शासनकाल में बिल्कुल नहीं होना चाहिये था । कभी कभी कहा जाता है कि अच्छा नहीं किया । अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत करो । बुरा भी आप करते हैं ।

हरिजनों के साथ नौकरियों के मामले में, शिक्षा के मामले में अन्याय होता होगा किन्तु उन पर अत्याचार क्यों होते हैं ? कुछ मामले मैं देता हूं । मुझे लगता है कि आजकल यह बीमारी जो बड़ी तादाद में बढ़ती जा रही है यह इस वास्ते कि हम भारी बहुमत से चुन कर आए हैं और इसकी वजह से मन में एक बात बैठ गई है कि मुझ को पूछने वाला कोई नहीं है । पुलिस भी ज्यादती कर सकती है । लेकिन गांव गांव में कौन करता है । जो हमने देखा है उनको मैं आपको सुनाता हूं । बावड़ा, जोकि पूना जिले में है, वहां क्या हुआ ? इसको मैंने कनसलटेटिव कमेटी में भी उठाया था । जिला परिषद के चुनाव को ले कर क्या हुआ ? पांच महीने तक हरिजनों का बहिष्कार क्यों किया गया है ? क्या सिर्फ इसलिए कि एक आदमी जो आज महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मंत्री है उसका भाई चुनाव लड़ रहा था और उसके विरुद्ध एक हरिजन खड़ा रहना चाहता था । मैंने स्वयं इस मामले को कंसलटेटिव कमेटी में उठाया है । मुझे बताया गया है कि इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है । मैंने जानकारी लेने की कोशिश की । मुझे पता चला कि अस्पृश्यता निवारण कानून के अन्तर्गत यह मामला दर्ज नहीं

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

किया गया है और ऐसा करने का कारण यह है कि उनको ज्यादा दण्ड मिल सकता था और सारे सवर्ण लोगो को इस में लपेटा जा रहा है । दादा वर्ग हर गाव में पैदा हो गया है जो रूलिंग पार्टी से सम्बद्ध है । उसको पता है कि हमे कोई पूछने वाला नही है। उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए वहा का थानेदार भी तैयार नही होता है। मैं अपनी कस्टिट्युएंसी की बात आपको बताता हू और नाम ले कर बताता हू । मेरी कंस्टिट्युएंसी मे जीरापुर मे स्वय हरिजनो ने मुझे आकर बताया है कि कोई हरिजन जा रहा था उसको कांग्रेसी नेता ने मारा पीटा । मैंने गाव वालो से पूछा तुम ने इसके बारे मे कुछ क्यो नही किया ? उसी रात को पब्लिक मीटिंग मे मैंने गाव वालो को पूछा तुम क्यो चुप बैठे रहे जो जुर्म करने वाला है उसको पकड कर पुलिस के हवाले क्यो नही किया, किसी को मारने की इजाजत चाहे वह नेता हो या कोई भी किसी को भी नही है, और जो जुर्म करता है उसको पुलिस के हवाले किया जाना चाहिये था । लेकिन वे बेचारे क्या कर सकते है घोड़े पर कोई जाए तो उसको कोडे मारे जाए और गरीब सहन करते रहे, यह नही हो सकेगा । मैंने गाव वालो को यह भी कहा है कि हर जगह पुलिस नही जा सकती है । आपको भी अन्याय को सहन नही करना चाहिये । गांव गाव मे पुलिस नही जाएगी । जब तक मन मे गन्दगी रहेगी पुलिस क्या करेगी ? गांव गाव में आपको जन जागरण करना चाहिये, क्रान्ति लानी चाहिये थी । परबनी जिले में औरतों को नंगा घुमाया गया । मैं पूछता हूं कि वे लोग क्या करते हैं, क्यों नही आगे आते हैं । लेकिन शासन उनको आगे नही लाया हैं । शिक्षा मे उसने उनको पीछे रखा हैं नौकरियो मे पीछे रखा है । यह जो आपने किया, इसको तो किया लेकिन कम से कम उन पर अत्याचार तो न होने दे और न ही आप उन पर अत्याचार करे । मैं चाहता हू कि जब कभी भी किसी घटना का शासन को पता चले, उसको तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिये । बावडा गाव की घटना के बारे मे मैंने कसलटेटिव कमेटी मे पूछा था और मुझे बताया गया कि उनके खिलाफ कुछ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लेकिन हरिजन कानून के अन्तर्गत नही हुआ है । मैं जानता हू कि उनको सजा कुछ नही होगी और ऐसे ही वे रिहा हो जाएंगे, छूट जाएंगे । कोई भी गलत काम करता है तो उसको दड मिलना चाहिये । पिछले पच्चीस साल मे उनकी शिक्षा की समस्या, उनके घर की समस्या, उनको नौकरियो मे लेने की समस्या आदि जो उनकी समस्यायें हैं उन मे से हम किसी को भी हल नही कर पाए है । अनटचेबिलिटी आज भी कहा कहा है और किस-किस रूप मे है, इसके उदाहरण बड़े मजेदार हैं । चडीगढ़ मे कमीशनर की रिपोर्ट मे बताया गया कि है जब एक हरिजन को यह मालूम हुआ कि हरिजन कहने से नौकरी नही मिलेगी तो किचनमेड की नौकरी के लिए उसने अपना नाम बदल दिया । यह अनटचेबिलिटी आज भी किसी न किसी रूप में चालू है । मैं चाहता हूं कि इन सब बातों की ओर शासन ध्यान दे और जो

उसका दायित्व है, उसको वह समझे। अन्याय जो उनके साथ होते हैं, उनको बन्द किया ही जाना चाहिये और अगर वह आप नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो करिये कि उन पर अत्याचार न हों। यह तो शासन के देखने की चीज है।

एक माननीय सदस्य : जनसंघ ज्यादा करता है।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह पार्टी का सवाल नहीं है। कोई भी करता हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिये।

श्री अनंत प्रसाद चूलिया (बस्ती) : शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट दो ढाई साल के बाद यहां पर प्रस्तुत की गई है और इतनी देरी से हम इस पर विचार कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि गवर्नमेंट ने इस ओर तत्काल ध्यान नहीं दिया और दिखावे के लिए इसको यहां रख दिया गया है। यह भी अधूरी है। इम्प्लेमेंटेशन रिपोर्ट भी साथ में नहीं रखी गई है। सोशल वैलफेयर का एक पेरेंट डिपार्टमेंट भी है जहां पर लोगों को कामकाज से कोई मतलब नहीं है, पार्टी बाजी और गुटबाजी पैदा करके ये लोग दिल्ली में रहने के चक्कर में रहते हैं और अपनी प्रोमोशन के चक्कर में हमेशा लगे रहते हैं। यह डिपार्टमेंट शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का ट्रस्टी या कस्टोडियन कहा जा सकता है लेकिन अगर कोई शैड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब का आदमी यहां भूले-भटके पोस्ट हो जाता है तो यहां के अफसर और यहां के गुटबाज लोग उसे निकालने के लिए विस्मयकारी षड्यंत्र रचते हैं।

आप जानते हैं कि 1969–70 की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। इसके पहले की दो रिपोर्टें जो थीं 1966–67 और 1967–68 की उनको भी मैंने पढ़ा है। बैकवर्ड क्लासिस कमिशन की रिपोर्ट काका साहेब कालेलकर द्वारा लिखी गई थी और शैड्यूल्ड कास्ट एंड शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की रिपोर्ट ढेबर साहब द्वारा लिखी गई थी। उनको भी मैंने पढ़ा है। पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इस में नवीनता कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इट इज नाट ए रिपोर्ट। ढेबर कमिशन की रिपोर्ट को आधार मान कर कुछ फेरबदल करके इसको प्रस्तुत कर दिया गया है। इस मे कोई नई चीज नहीं है और न कोई नया प्रयास है और न नया विचार है। जिन डिसएबिलिटीज से ये लोग सफर करते है या जिस तरह से इनको इनफीरियर समझा जाता है, उसको रिमूव करने के लिए कौन सी स्कीम बनाई गई है या कौन सा टारगेट रखा गया है, इसके बारे में इस में कुछ भी नहीं है। उनकी डिसएबिलिटीज को दूर करने के लिए जो कठिनाइयां सामने हैं उन कठिनाइयों का हल निकालने के लिए कौन सी स्कीम्ज बनाई गई हैं, उसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं है।

आप जानते हैं कि हरिजनों तथा शैड्यूल्ड ट्राइब्ज में कुछ क्वालिटीज भी हैं। उनकी सिंसेरिटी, उनकी आनेस्टी उनकी हार्ड

[श्री अनंत प्रसाद चूलिया]

लेबर, उनकी इंटेग्रेटी सब को मालूम है । उनकी क्वालिटीज और सोशल वैल्यूज को आधार मान कर क्या कोई स्कीम्ज उनके लिए बनाई गई हैं ताकि इनफीरियारिटी और डिसएबिलिटीज दूर हों, यह मैं आप से जानना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि ऐसे इम्पार्टेंट प्वाइंट्स पर कुछ भी नहीं कहा गया है । क्या यही सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट और शैड्यूल्ड कास्ट्स एंड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट है ? इस रिपोर्ट से अच्छी रिपोर्ट अगर चार छः या दस इंटेलीजेंट आदमी मिल कर बैठ जाते तो तैयार कर सकते थे और वे उस में न्यू वैल्यूज को स्थान दे सकते थे ।

इस डिपार्टमेंट के आफिसर्ज ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को तो पायंट आउट किया है, लेकिन उन लोगों ने कोई इम्मीडिएट सालूशन या इम्मीडिएट रिलीफ देने के लिए कोई स्कीम नहीं रखी है जिस से उन की इकानोमिक और सोशल कन्डीशन में त्वरित सुधार हो । इस तेजी से बदलती हुई ऐज में उन की क्या नीड्ज हैं उन को क्या गाइडेंस और प्रोटेक्शन चाहिए इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, इस तरह से कागजी पतंग उड़ाने से किसी देश, रेस या जाति का सुधार नहीं हो सकता है ।

इतना ही नहीं, देश की आबादी का सातवां हिस्सा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का है ।

एक माननीय सदस्य : चौथा हिस्सा ।

श्री अनंत प्रसाद चूलिया : समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की उपेक्षा से उन लोगों का सुधार कैसे हो पायेगा । अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म तथा प्रेजुडिस समाज के हर एक हिस्से को प्रभावित कर चुके हैं । इस का परिणाम यह है कि इन गरीबों के लिए मिट्टी खोदने या कोई अनक्लीन प्रोफेशन एडाप्ट करने के सिवाये कोई दूसरा चारा नहीं है । वे जिस दायरे में रहते हैं, उसी दायरे में उनको परेशान किया जाता है । शोषण, व्यभिचार, बेगार, कत्ल और जिन्दा जला देने का सिलसिला सदियों से चला आ रहा है । क्या उन की कठिनाइयां अन्तहीन हैं, कभी कभी मैं यह सोच कर इमोशनल हो जाता हूं ।

मुझे मालूम हुआ है कि 1967 से 1969 तक की तीन साल की अवधि में 1100 हरिजन मार डाले गये—किल्ड, मर्डर्ड और बुचर्ड । मुझे तो यह भी सूचना मिली है कि कुछ हरिजन एम० पीज० और एम० एल० ऐज० को भी मार डालने की धमकी दी गई है । इस रिपोर्ट में इन ज्यादतियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है ? कुछ है इस में ? क्या मंत्री महोदय मुझे बतायेंगे कि क्या इस में कुछ है ? जहां तक मैं ने पढ़ा है, इस में कुछ नहीं है ।

इस से यह स्पष्ट है कि इस डिपार्टमेंट में कोई मिशनरी स्पिरिट नहीं है, न कोई स्पानटेनियटी है, न कोई अर्ज है और न इन्टरेस्ट है । ये लोग अपनी रोजी कायम

रखने के लिए खानापुरी कर रहे हैं । सदियों से सताये हुए इन करोड़ों व्यक्तियों के खून के आंसू आप कब तक रोक पायेंगे ? इन्साफ़ तो बड़े आदमियों को मिल रहा है । और इन गरीबों को क्या मिल रहा है, इसे आप जानते है । उन की जान के लाले पड़े हुए हैं । इस देश में न दबी हुई जातियों को दबाने की परम्परा सदियो से कायम है और इस में उच्च वर्ग, नौकरशाही, सामन्तवादी और पूंजीपति सभी शामिल हैं । जब गवर्नमेंट की तरफ़ से कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है कि उन मे कुछ सुधार हो, ...

MR DEPUTY SPEAKER: The hon. Member may try to conclude now.

SHRI ANANT PRASAD DHUSIA: Yesterday, some Members were given 30 minutes. It is not even 15 minutes ...

MR DEPUTY SPEAKER: I have 33 names from the Congress party. Even if I give 10 minutes each, it means six hours. I am trying to restrict time to 10 minutes each.

AN HON. MEMBER: The time allotted is 10 hours.

MR. DEPUTY SPEAKER: Out of 10 hours, some time was taken yesterday .... (*Interruptions*). Order please. I am trying to tell you that ten hours have been allotted. That is true. Yesterday some time has been taken, maybe two hours or so . So, eight hours are left out. We have got 33 names from the Congress Party. Even if I give ten minutes each, it means about six hours out of eight hours. Then what about the Opposition? Will they not have some time? I am just drawing your attention to this.

श्री अनंत प्रसाद धूसिया : नौकरशाही, पुलिस, सामन्तवादी और बड़े-बड़े जमींदार मिल कर किसी भी काम को सफल नहीं होने देते हैं ।

यहां पर शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के एम० पीज० बैठे हुए हैं । ये कब तक अपने भाई-बन्धुओं का खून और अपनी मां-बहनों की बेइज्जती देखेंगे ? ये ऐसे इन्सानों के प्रतिनिधि है, जिन का जीवन एक सूखी लकड़ी के समान है, जो कभी भी अपने आप को जला कर समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं । वे बंगला देश और वियतनाम की कहानियां सुन चुके हैं ।

इस लिए मेरा निवेदन है कि शिडयूल्ड कास्टस कमिश्नर की रिपोर्ट को फिर से लिखा जाये । इस में कोई नवीनता नहीं है । इस को शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज के प्रतिनिधियों की सहायता से बनाया जाये, केवल ब्यूरोक्रेसी की सहायता से नहीं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now; please conclude.

SHRI ANANT PRASAD DHUSIA: Most of my speech is left out.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You should have organized it within the time available. If I give you more time, it means the other Members' time will be cut down.

श्री अनंत प्रसाद धूसिया : अनटचेबिलिटी एक ऐसा स्टिग्मा है, जिस के रहते हुए आप कितनी ही समाजवाद, राष्ट्रीयता और एकता की बात करें, शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज को वह फीकी लगती है। जब तक यह चीज खत्म नहीं हो जाती है, तब तक इन बेबस इन्सानों के लिए समाजवाद, राष्ट्रीयता और एकता के क्या मानी हैं, इसे आप ही बतायेंगे।

किसी भी उपेक्षित जाति को ऊपर उठाने के रास्ते में ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बड़ी बाधा हैं। शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्ज को ऊपर उठाने के लिए इस बारे में कोई स्टेप नहीं लिया गया है। आप जानते हैं कि शिडयूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज में बहुत सी लड़ाकू और बहादुर कौमें भी हैं। राजस्थान की कौन सी ऐसी लड़ाई हुई, जिस में भील शामिल नहीं हुए? पूर्वोत्तर भारत में नागा ऐसी कौम है, जिस ने सभी लड़ाइयों में खुल कर हिस्सा लिया। इसी तरह से गोंड और मुंडा भी बहादुर जातियां हैं। परन्तु आपको मालूम है..

MR. DEPUTY SPEAKER: Now, there is no sign of your conclusion. You are going into the martial traditions of the Scheduled Castes. Please conclude.

श्री अनंत प्रसाद धूसिया : तो मेरा यही निवेदन है कि इन लोगों के लिए कोई ऐसा कदम उठाया जाय जिस से कि इन का भला हो और इस तरह से यह जो रिपोर्ट रखी गई है इट इज़ गुड फार नथिंग।

16.00 hrs.

SHRI SANGLIANA (Mizoram): I consider it auspicious that the very first time I speak in this august House, I do so on the subject of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, a subject in which I am personally and deeply involved, being a tribal myself.

As I go through the observations and the recommendations with which the report and its discussion is introduced, I find it apparent that the utmost care has been taken to get to the root of the problems that confront the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and to remedy them as best and as quickly as possible. After what we see in the report, one can say almost without fear of contradiction that the minorities in India and, especially, the backward sections like the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, get as fair a deal as any minority gets in any other part of the world, at least constitutionally, if not actually. We, who belong to this group, acknowledge that gladly, and we find much comfort in the knowledge that the aim of our Constitution set before the people of India is the protection of the weaker sections of the population from social injustice and all forms of exploitation.

A careful consideration of the report under discussion, however, shows that much that has been provided for to safeguard the interests of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, has not shown the desired and the expected result, and there is still a wide gap between what is proposed and provided for and what is actually achieved and implemented. If I may hazard a guess, the reason why the various schemes, programmes and provisions for effecting progress and development of the backward communities have not succeeded, as they should, is to be found in the fact that the implementation and working out of such schemes and programmes at some stage or other, falls into the hands

of people who lack in imagination and who do not realize the importance of the responsibility that is theirs and who merely carry it out as a matter of official routine with little real concern for the welfare of the people, and the result is that to-day, after 25 years of Independence and 25 years of "special programmes, consideration and endeavour for their upliftment", the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are still backward and are still very much in need of special measures and treatment.

I would now like to turn in particular to Mizoram, the territory from which I come I am sorry to say that in the report there is very little mention made of Mizoram, in fact, except for a casual reference to the high percentage of literacy and the fact that it was one of the Districts in Assam with an autonomous District Council, there is hardly any other mention of Mizoram or the Mizo people

I take it not as a sign of wilful neglect for Mizoram but as an unintentional oversight which nevertheless is unfortunate although not intended. Mizoram is perhaps really the least known part of India. If we are to find reasons for this, one could be found in the fact that communication in Mizoram was so poor, it was not visited by people from outside except for the most important, pressing and unavoidable official duties. Even after 20 years after independence Aizawl the capital of Mizoram was still unconnected by an all-whether road It was only when the Border Road Task Force undertook the construction of the road after the outbreak of disturbances in Mizoram in 1966 that Aizawl was connected with Silchar by an all-weather road. Mizoram has, as you perhaps already know an international boundary with Burma, running almost into 200 miles or so and aout 100 miles with Bangla Desh. It has no air service though there is an airstrip which was constructed since 4 years ago by the Defence Ministry.

I would like to take this opportunity of suggesting that an air service should be opened up and we are sure that that can be done if the present airstrip is repaired and improved. It will be definite boon to Mizoram if the air service can be started. If communication to Aizawl was difficult the position of Lunglei and Salha in Pawi-Lakher region still 140 and 190 miles further away respectively can be easily imagined. In undivided India, Lunglei, the southern part of Mizoram, used to be served by Chittagong just as Aizawl was served by Silchar. If Government can make an arrangement whereby essential commodities and other articles of trade can be transported through Chittagong to Lunglei it will undoubtedly benefit the people of southern Mizoram.

Now, Sir, those of my friends whom I have met here in Parliament have said that Mizoram is very progressive in the educational field. They had exaggerated opinion about the educational progress that we have made and I think that has been caused by the fact that our literacy percentage is fairly high, being 50.9 per cent. If we were to be guided simply by that, it would be a wrong judgment. We still lack very much in higher education. We have just three colleges One of these is a full-fledged Art College. The other is not even full-fledged yet. The third one is only one year old. We don't have any provision for the teaching of science in any of these three colleges now. That is the position. We are still backward so far as higher education is concerned. Honours courses even in art subjects have yet to be introduced. However, in spite of all these handicaps, the Mizo boys and girls have quite often topped the lists in various subjects in the Gauhati University

[SHRI SANGLIANA]

which they have mostly been attending. But I am sorry to add that no student has so far, at least to my knowledge, been enabled to proceed for doctorate by award of scholarships. I think that this may please examined and rectified.

I want to bring to your notice again the fact that in games also our tribal boys have shown talents. It may be recalled that in spite of the lack of coaching facilities, the tribals have shown in the field of games. When we speak about these games, one begins to think of T.Ao who had the distinction of captaining the Olympic football team once. I would like to recall also the name of the late Shri Jaipal Singh who captained the Indian Hockey Olympic team in Los Angeles in 1932. Today, if I may mention, the only Hockey team from the eastern part of India is made up of players from Mizoram, nine of them being from Mizoram itself, while one is a non-tribal and the remaining player is a tribal from Bihar. When our Indian Olympic Hockey team failed to come back with the gold medal this year there was a murmur of regret amongst the young Mizo hockey-players, and they felt that if they could be associated more and if they could be given better coaching facilities, it would be the greatest incentive for them to win the gold medal back for India.

Sir, it will certainly be a stop forward in the process of integration, if more scope and chances are given to the tribal people for participation in the all-India games. The fact that even today there is a team of football players from Nagaland who have done very well in their first two matches is certainly a good thing, and if we are to get the people really friendly with the rest of the people in India, matches of this kind can be arranged more frequently and more opportunities should be given to us.

I just want to bring to your notice one fact which I feel has often been overlooked. The reason why we the Mizos, for example are not so well known as the Nagas is that we lack spectacularity in dress and culture, because a lot of our culture lies in the inner life, so to say, and when Christianity is coupled with this, we are often misunderstood and are often considered to be sophisticated and perhaps non-tribal. I say this because of what chapter 16 of the report says. There is a suggestion there from the Joint Committee of the two Houses of Parliament that no person who gives up tribal faith and embraces Christianity or Islam shall be deemed to be a member of any Scheduled Tribe. This suggestion, I submit, fails to take cognizance of the fact that it takes much more than a faith or faiths to constitute a tribal. In Mizoram, for example, 90 per cent have accepted Christ's teachings and have become Christians. The Christian Church has come to stay there, whatever the future may bring. If this suggestion is to be accepted then not even 5 per cent of the Mizos will be treated or will be counted as tribals.

I submit, and strongly so, that Christianity is not spoiling our tribal self-hood, as is sometimes alleged, and we do not get detribalised when we become Christian. Christ's teaching has not taken anything of value from our tribal life. *Tlawmngaihna*, the code of our social behaviour so highly prized by every Mizo, gains strength, support and refinement when enforced by Christianity. Christianity enriches the tribal life culturally and inwardly but does not bestow economic prosperity. The suggestion to detribalise a person on his accepting Christianity defeats the very idea of helping him to catch up with the rest of the people of India, and will only prolong his economic and even social backwardness.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let him conclude now.

SHRI SANGLIANA: As the time is up.....

MR. DEPUTY-SPEAKER: More than up. I think you have made your point.

SHRI SANGLIANA: I would only take this opportunity of suggesting that an increasing association of members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all stages of implementation of measures that are intended to benefit them should be a very useful step forward.

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन की 1969–70 की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए और उस पर अपने ख्यालात रखने के लिये आपने मुझे जो वक्त दिया है, उसके लिये मैं आप का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं ।

हिन्दू समाज छूआछूत और हरिजन समस्या के कोढ़ को लेकर बहुत सदियों से अपने ऊपर कलंक लिये हुए चला आ रहा है । इस सम्बन्ध में हमारे पुराने महापुरुषों से व संतों तथा पं० जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है । आज यह जो कलंक हिन्दू समाज पर है, वह हमेशा के लिये मिट जाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि यह इतना पुराना रोग है कि उसका इलाज इतना आसान नजर नहीं आता है ।

हम शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने हरिजन उत्थान के लिये जो लहर चलाई है, उसके लिये अहसान-फरामोश नहीं होना चाहते हैं और हम जानते हैं कि अगर सुधार की यही रफ्तार चलती रही तो जरूर एक दिन इस समस्या का निबटारा हो कर रहेगा और यह कलंक मिट के रहेगा । हिन्दुस्तान के अन्दर जो हरिजन वर्ग है, अनुसूचित जातियां हैं—ये सदियों से पिछड़ती चली आई हैं, इन लोगों में जो एक मेहतर वर्ग है, सफाई करने वाले, उन की व्यवस्था तो आज भी ज्यों-की-त्यों है, इतनी गिरी हुई है कि उस का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है । उस में राजनीतिक शक्ति नहीं है, आज भी उस के घर वालों के पास, कूड़ा-करकट ढेर के पास बनवाये जाते हैं, कोई उस का पुरसां-हाल नहीं है । म्युनिसिपल बोर्डों में भी मेहतर भाइयों के अन्याय, दुख-दर्द का अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है । मैं बड़े अदब से आप के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मेहतर समाज के साथ इसी तरह से लापरवाही होती रही तो एक दिन सारे हिन्दुस्तान को इस का परिणाम भुगतना पड़ेगा । सफाई कर्मचारियों की ओर विशेष ध्यान सरकार का जाना निहायत जरूरी है ।

उपाध्यक्ष महोदय, देहातों के अन्दर, शहरों और कस्बों के अन्दर आज भी छुआछूत कायम है । यह ठीक है कि शहरों और कस्बों के अन्दर कुछ कम हुई है, लेकिन आप देहातों में चले जाएं तो आप पाएंगे कि छुआछूत का सांप और ज्यादा तगड़ा बना हुआ है, उसने पहले से ज्यादा पैर जमाना शुरू कर दिये हैं । आज भी हिन्दुस्तान के गांवों के अन्दर छुआ छूत की बीमारी कायम है और यह

[श्री हरी सिंह]

बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है, बल्कि एक तरह से वहां पर एक विषाक्त वातावरण बन गया। छुआछूत घटती नजर नहीं आती है।

आप जानते हैं सदियों से हरिजन भाई सूद-खोरों के चंगल में फंसा रहा है, आज भी जो पूंजीपति हैं, वे उसको कर्ज देकर जिन्दगी भर के लिये उसको अपना गुलाम बना लेते हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। अगर आप हरिजन भाइयों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो सरकार 5 हजार रुपये तक की धनराशि उन को ब्याज मुक्त कर्ज दे। उस कर्ज की जमानत के लिये उसकी सम्पत्ति या मकान की हैसियत का पैमाना न लागू किया जाये। बल्कि उस शर्त को हटा कर सिर्फ दो आदिमियों की जमानत पर उसको यह कर्ज दिया जाय, वरना यह "बाण्डेड लेबर" की प्रथा चलती रहेगी। यह बिना पैसे की मजदूरी और बेगार चलती रहेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हू कि अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो बिना ब्याज के उनको ऋण देने की व्यवस्था की जानी चाहिये। आज आप जानते हैं कि सारे समाज में परिवर्तन आ रहा है लेकिन बिना आर्थिक प्रगति के, वह परिवर्तन हरिजन समाज में नहीं आ सकता है। कोई भी समाज ऊंचा उठ नहीं सकता है जब तक कि उसकी माली हालत को ठीक न किया जाये, आप जानते हैं कि हरिजन भाई बड़े बड़े कल कारखाने अपने पैसों से खड़े कर सकें यह एक असम्भव बात है। आज यह मुमकिन नहीं है कि हरिजन भाई बड़े शहरों जैसे कलकत्ता, बम्बई में जाकर बड़े बड़े कारखाने लगा सकें। उनको तो छोटे पैमाने पर ही अपना काम करना पड़ेगा। आज आप जानते हैं कि बड़े बड़े कारखानों से ली हुई चीजों की एजंसियां होती हैं अगर वह हरिजन भाइयों की कोआपरेटिव सोसायटीज को दी जाय तो उनकी आर्थिक दशा में सुधार आ सकता है। लेकिन आज तो जितने भी कोटा परमिट और लाइसेंस होते हैं जिनसे कि हरिजनों की अवस्था में आर्थिक सुधार लाया जा सकता है वे सभी कोटे बड़े-बड़े आदमियों के हाथों में ही चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के भी आर्थिक सुधार होने की सम्भावना नहीं हो सकती है।

आज आप जानते हैं कि देहातों में और सारे देश में जमीन के बटवारे की बात कही जा रही है और यह कहा जाता है कि हरिजनों को जमीन दे दी गई है। लेकिन यह काम जिला-परिषदों, ब्लाक आफिस, पचायतों और सरपंचों को दिया गया है। वे लोग तो यह समझते हैं कि यह जमीन हमारे घर से जा रही है। आज उनके मन में उपकार की भावना नहीं आती है। वे यह समझते हैं कि यह जमीन उनसे छीन कर हरिजनों के पास जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जमीन के बटवारे का काम, हरिजनों के कल्याण का काम, हरिजनों की भलाई का काम जो भी है वह सीधे सरकार के हाथ में होना चाहिये। जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों के हाथ से इस काम को ले लेना चाहिये। क्यों कि उनको इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। वे इस समस्या को गम्भीरता से नहीं

How do you except the Speaker to

होचते हैं, बल्कि उनके दिल में एक प्रकार की जलन होती है।

जैसा कि हमारे दोस्तों ने यहां पर जिक्र किया, हिन्दुस्तान में हरिजनों पर अत्याचार हुये हैं, कत्ल हुये हैं और उनके साथ बलात्कार किया गया है। ऐसी घटनायें प्राय: हमें अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि अत्याचार पहले भी होते थे लेकिन मौजूदा समय में, हम तीन चार सालों में हरिजनों पर अत्याचार और जुल्म बहुत बढ़ गये हैं। उनके प्रति इन अन्यायो और अत्याचारों की कहानी बहुत गम्भीर और काली बनती चली जा रही है। आज हमारे नौजवानों और अछूतो के मन मे इन बातो को लेकर विद्रोह की भावना पैदा हुई है। आज वे बगावत पर उतारू हैं। यदि हिन्दू समाज ने अपनी न भावनाओं को नही बदला तो हिन्दुस्तान के अछूत भाई सारे समाज के ढांचे को तोड़ डालगे और कहेंगे कि हमको भी इनसान मानिये। वे भी इनसान है, एक जानवर की तरह से उनको दूर नहीं किया जा सकता—इस बात को बर्दाश्त करने के लिये वह तैयार नही हैं। आज हिन्दुस्तान में जो सारी बात चल रही हैं वह उनके लिये काबिले बर्दाश्त नहीं है

यदि आज आप दफ्तरों में जाकर मुआइना करें तो देखेंगे और ताज्जुब करेंगे, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टोरेट का हाल यह है कि वहां पर टूटी हुई कुर्सियां हैं, पुरानी बिल्डिंग जिसमें हर साल पानी चूता है, न तो वहां पर स्टाफ मौजूद है और न फाइलों को रखने के लिए वहां पर कोई अलमारियां हैं। किस प्रकार से वहां पर काम होता है, यह मेरी समझ मे नहीं आता है। उस दफ्तर के साथ सौतेली मा जैसा बर्ताव किया जाता है। उन्हें सारे साधन उपयुक्त मात्रा में नहीं दिये जाते हैं।

जहां तक हरिजनों का सारे देश में नौकरियों का कोटा पूरा करने का सवाल है, मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि किसी भी विभाग में, जो कोटा रिजर्व है उसको पूरा नहीं किया गया है। तरह तरह के बहानो को लेकर उसको टाल दिया जाता है। यहां पर सिविल एविएशन के मंत्री महोदय बैठे हुये हैं मैं उनके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि खास तौर पर सिविल एविएशन, इण्डियन एयर लाइन्स में उस कोटे की पूर्ति नही की गई है। मैंने मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ लिखित रूप से खीचा था। और पर्सनली भी उन्हें इन हालतो से अवगत कराया था। वहा पर यह देखा जाता है कि घुंघराले बाल हो, सुन्दर नाक हो, रंग गोरा हो और खूबसूरत हो लेकिन अछूत जाति के नौजवान इतनी खूबसूरती कहां से लायें। अत: उन्हे नौकरी में नही चुना जाता है। मैं दूसरे महकमों की तरफ इशारा नही करना चाहता, चूंकि मंत्री जी वहां पर बैठे हैं इसलिये उनके विभाग के सम्बन्ध में कह रहा हूं। इस विभाग की हालत बहुत खराब है। वहां पर हरिजनों की तरफ कोई तवज्जह नही की जाती। बड़ी पोस्ट के लिये तो हरिजनों में सूटेबल आदमी नहीं मिलते

[श्री हरी सिंह]

का बहाना करते हैं और छोटी टेस्टों के लिये भी विभाग की तरफ से मनमानी की जाती है। एक पक्षपातपूर्ण रवैया चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि सारे विभागों में हरिजनों के कोट को पूरा करने के लिये पार्लियामेंट के मेम्बर्स का एक बोर्ड बनाया जाये जोकि हर विभाग की छानबीन करे कि वहां पर वांछित संख्या में भर्ती हुई है या नहीं। इस प्रकार का कोई बोर्ड या कमिशन अवश्य बनाया जाना चाहिये।

बॉंडड लेबर की प्रथा उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े पमाने पर चल रही है। इसको समाप्त करने के लिये सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। हमारा यह प्रयत्न होना चाहिये और देखना चाहिये कि अगर हमारे अछूत भाई ऊपर नहीं उठते हैं, इस देश के शेड्यूल्ड कास्ट भाई तरक्की नहीं करते हैं तो हिन्दुस्तान भी तरक्की नहीं करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज सेना जो जीत पाई है उसमें भी हरिजन भाइयों का बहुत कुछ हिस्सा रहा है। हमारी यह जीत सम्भव नहीं होती अगर हमारे हरिजन भाई खेतों में हल नहीं चलाते। आज भी हमारे हरिजन भाई अगर देश की तरक्की के लिये अपना खून पसीना नहीं बहाते तो देश तरक्की नहीं कर सकता था। एशिया फेयर के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हजारों मजदूरों ने, जिनमें 90 प्रतिशत हरिजन थे, दिन रात काम करके यह खूबसूरत नुमाइश तैयार की है। मुझे प्रसन्नता है कि उद्घाटन के अवसर पर हमारी प्रधान मंत्री महोदया का ध्यान उनकी तरफ गया, उन्होंने उनके सम्बन्ध में भी कुछ बात कहीं। और उनके उत्साह के लिये उन्हें भी उद्घाटन के अवसर पर धन्यवाद दिया। इससे हरिजन मजदूरों के मन में प्रसन्नता की आशा आई।

ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहता हूं कि अछूतों की समस्याओं को हमें गम्भीरता से समझना होगा और उनको हल करने का प्रयत्न करना होगा। अन्त में स्वामी विवेकानन्द के शब्दों को दोहराते हुये अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं कि ऐ मेरे भारत-वासियों, तुम हर एक चमार को, ब्राह्मण को, मेहतर को हिन्दुस्तान का वासी समझो, सारे भारतवासी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारा रक्त है, खून है।

SHRI R. P. ULAGANAMBI (Vellore): While discussing the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes 1969-70, I should like to bring to your notice certain important points which need consideration. The report for 1969-70 was submitted in the end of 1971 and is being discussed now, end of 1972. I do not know the reason for such inordinate delay in submitting the report and in discussing it.

At the outset I should say that the social welfare portfolio is now attached to the Ministry of Education; formerly it was with law. If this portfolio is attached to some other department, it loses its importance and effectiveness. I submit that it might be separated from other portfolio and upgraded to the level of a separate Ministry in the charge of a State Minister under the direct control of the Prime Minister so that it may become effective.

The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is appointed by the President under article 338 of our Constitution. He is free to receive any complaints and collect relevant records and the SC/ST employees are free to approach the Commissioner for SC/ST and bring their complaints to his notice. But in his report, chapter 10, para 12, the Commissioner says:

> "In the absence of these instructions to the authorities concerned, it is not at all possible for the Commissioner to do justice to the duties entrusted to him under the Constitution."

I raised this point during the discussion on demands for grants of Social Welfare Department for 1971-72. The Commissioner for SC/ST is 28th warrant of precedence, equivalent to the Secretary to the Government of India. His rank should be made equal to that of the Chief Election Commissioner or the Chairman of the Union Public Service Commission i.e. 25th warrant of precedence. Then only he will be able to exercise his independent judgment in the discharge of his duties.

The Commissioner was originally assisted by the Assistant Commissioners in all State capitals. Now those posts have been abolished. He is helped by 5 zonal directors who are under the control of the Director General of Backward Classes. The Commissioner is helpless and unable to discharge his functions. When I made this point during the discussion on the Demands for 1971-72, the then Minister Shri Siddhartha Shankar Ray asserted that if the new Commissioner liked to have an Assistant Commissioner in each State capital, he could have it. I would like to know from the Deputy Minister who is present as to what happened to that assurance. The Minister of Education and Social Welfare is not present. This seems to the importance the Government attaches to this debate.

According to the directive principles contained in article 45 of our Constitution, education must be free and universal. Article 46 says that the State should take special care to promote the educational and economic interests of the scheduled castes and scheduled tribes. More than 20 years have passed since the Constitution came into force. How far have we achieved this objective. Government should take the necessary steps to achieve this objective.

The Commissioner has stated in Chapter 11 that the rates of pre and post-matric scholarships are extraordinarily low and the income limits not sufficient to cover all the deserving cases. The post-matric scholarship amount was fixed 20 years back and I regret to say that it has not been enhanced Replying to the discussions on the demands of this ministry for 1971-72, the then Minister, Shri Siddhartha Shankar Ray asserted that there was some substance in this criticism. But so far the Government of India has not taken any step to enhance this scholarship. So, I would request the Government to take radical and immediate action to enhance it, because it is very necessary at this juncture It is true that the children of scheduled castes and tribes have no alternative source of guidance. Poverty and ignorance of the parents of scheduled castes and tribes children may be termed as the major handicaps in the educational development of scheduled castes and tribes. Therefore, to improve their standard of education and economic condition. Government should start balwadi schools, i.e. nursery schools, so that from the very beginning the Harijan children may take interest in studies.

The number of foreign scholarships awarded to scheduled castes and tribes is also very low. In 1968-69 it was

[SHRI R. P. ULAGANAMBI]

only 8 out of a total of 323 scholarships. In 1969-70 it was only 11 out of 323. In 1970-71 it is only 5 out of 300. What is the mode for selecting these students? Why is it that such a small number of students belonging to these communities are selected to sent abroad? You are asserting that the students belonging to the Scheduled Castes and Tribes should come up educationally, economically and otherwise, at the same time, you are selecting only a few people belonging to these communities. So, due attention should be paid to this problem. There is also inordinate delay in selecting candidates for being sent abroad. For the year 1971-72 the applications were called for and many people applied. They have not yet been called for interview even though 1972 is coming to an end. The Minister should take action in this regard also.

Coming to untouchability, both the Central and State Governments have been taking certain measures to remove it. It is abolished by the Constitution and there is an Act to punish untouchability. Recently, Parliament amended that Act to make it more effective. Still, I regret to say, it is prevailing not only in the villages but also in the cities.

In Chapter VIII the Commissioner refers to discrimination against members of the Scheduled Castes and Tribes. He has specifically mentioned some incidents. In Delhi, the capital of our country, on 11th November, 1972, a Harijan youth of Firozabad was detained by the police for suspected pick-pocketing. It is reported that the boy was very badly ill-treated and tortured by the police. Two months back a harijan girl called Prem Latha of Kasthur Bhai Vidyalaya died under mysterious circumstances. In fact, a commission has been appointed to go into this matter in detail. It is reported that she was induced by the Principal to commit suicide. Another report is that she was beaten to death and thrown into the well. In Rajasthan 10,000 harijan families are feeling insecure because of the atrocities of the caste Hindus. From Punjab we hear the heartrending story of a 16-year old girl being paraded naked in the streets on the point of the sword by the caste Hindus. There is also a report about the death of three girls in Nabha. What action has been taken by the Punjab Government in this matter? In Orissa there was the report of 2,000 *Adivasi* girls being sold by the contractors. This matter was discussed in this House also. We want to know what action has been taken by the Orissa Government. In UP a group of women from Manoharpurva village met the District Magistrate and said that their daughters and daughters-in-law are not feeling safe. They said "our husbands and sons cannot save us; the government is deaf. Where do we go? Because there are cases of rapes, assault and murder?" It is reported that a group of women met the District Magistrate and gave a petition to him. It is in U.P. The name of the village is Manoharpurva village. Such is the state of affairs.

I am quoting certain important incidents. There are hundreds and hundreds of cases occurring daily in our country, in these modern days. We are living in an atomic age. The man reaches the moon. But here, we are practising and preaching in the name of caste, in the name of a particular sect of people, separated and segregated from society. Such incidents never occur in America or in Africa. Never such atrocities are committed on Negros. These days, Negros are not sold in the market. Once they used to be sold as chattel. But not now. That has been stopped now. Here, in our country, in a democratic republic country, after 25 years of having the Constitution, guaranteeing constitutional rights to Scheduled Castes and Scheduled Tribes people, such incidents occur daily. I would like to know from the

hon. Minister what steps have been taken by the Government to prevent such unhappy, unwarranted and uncivilised things happening in the society. What action has been taken by the Government against the culprits? The hon. Minister should contact respective State Governments to find out whether the culprits have been brought to book and punished.

In U.P., particularly, there are separate messes in college hostels for the students coming from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Even in police training institute, there is a separate mess for Harijan students. It is the duty of the State Government as well as of the Government of India to take action as to why they are allowing a separate mess for Harijan boys.

Even now, there are separate wells for Harijans. From a common well, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people are not allowed to take water They are not allowed to enter into temples

Now, I want to point out another thing about night soil. A particular sect of people are allowed to carry night soil on their heads Is it not shameful to make them carry night soil on their heads? Why not the State Government or the Central Government take necessary action immediately to stop night soil being carried on a head? Even a mother of the child hesitates to take night soil of her child. But a particular sect of people are allowed to carry head-loads of night soil. Neither the State Government nor the Central Government has taken any action against that. I urge upon the hon. Minister to take appropriate action to stop the carrying of night soil by a particular sect of people on their heads.

You have to remove all those barriers of untouchability, caste system and all that. You are following only the traditional customs and conventions. You only talk on the platforms but not take any proper action about it. There are certain measures suggested by the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in his Report. Nowhere in India, in any city, either in Delhi or Bombay or Calcutta, a Harijan becomes a Mayor. In Madras, there is a convention followed that by rotation a Harijan becomes a Mayer.

There is a roster-Brahmin, non-Brahim, Harijan, etc.—and their is a chance for a Harijan to become a Mayor. Why not follow this practice all over India, in all other big cities? The Central Government should ask State Governments to follow such a convention so that Harijans get a chance to become Mayors in all big cities of India, including Delhi.

There are Governors in India, but none of the Governors belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe There are many Ambassadors from our country, but non of them is from Scheduled Caste or Scheduled Tirbe. Are they not competent to become Govenors of Ambassadors or Mayors? Is Prof. R. D. Bhandare, the legal luminary, not competent to become a Governor? is Mr. B. S. Murthy not competent to become an Ambassador? I request the Government through you, Sir, that they should appoint Governors, Ambassadors and Mayors from Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

There are 114 MPs belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in this House. But I do not know how many MPs belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are in the Rajya Sabha; I have given a note in the library; I do not know how many are there I do not know how many Members are there in the Legislative Councils belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is a Constitutional guarantee given in the case of Lok Sabha and Assemblies. But there is

[SHRI R. P. ULAGANAMBI]

no such guarantee in the case of Rajya Sabha as well as Legislative Councils, so that the Ruling Party does not care to allow Scheduled Castes and Scheduled Tribes to become Rajya Sabha Members or Council Members. I would like to know how such barriers can be removed.

How are we to remove untouchability? We are talking about untouchability but not about caste system. Caste system is the root cause of untouchability. There is a difference between untouchability and caste system. Hon members and political leaders should realise this We are talking about untouchability, but we have forgotten about caste system. Caste system is the root cause of untouchability. That is why Dr. Ambedkar used to say—and he has written many books—about annihilation of caste system. Gandhiji and other political leaders also have talked about it. Hon members should realise this: if untouchability is to be removed, then we should remove the caste system. That is why, Dr. Ambedkar insisted on annihilation of caste system. Our former Chief Minister of Tamil Nadu, *Arinagar Anna*, also insisted on that. Our present Chief Minister, Shri Karunanidhi, and the leader of Dravida Kazhagam, Shri E. V. Ramaswami, are also insisting on abolition of caste system. Certain steps should be taken for this purpose. We should encourage inter-caste marriage. Our State is encouraging inter-caste marriage. We are giving awards, gold medals, to the couples who marry inter-caste. Our Chief Minister's son will be getting married on 10th December to a Harijan girl Dr Ambedkar married a Brahmin girl. The son of Gandhiji married the daughter of Rajaji. If the political leaders really want to annihilate the caste system they should encourage inter-caste marriage by giving incentives like gold medals, cash payment, job opportunities, loans to carry on their profession, etc.

SHRI D. BASUMATARI (Kokrajhar): While my predecessor was speaking, I was listening to him with rapt attention. I submit that instead of wasting his energy here in the Centre, he should exert efforts with the State Government which is run by his own Party. I do not know whether he has done that or not.

Now, coming to the report, every time we discuss this report but noting comes out. The purpose of Art 338 which was incorporated by the Constitution-framers at the instance of Mahatma Gandhi is to ameliorate the conditions of the down-trodden people and bring them to the level of the other advanced sections of the community within a stipulated time. Our National leaders are also anxious to bring them to the same level that Mahatma Gandhi had envisaged. A lot of sentiment and emotion was expressed here. But when we go from here, we forget I had been feeling, when my friends were speaking with emotion, that nothing will be done Unless we do it ourselves, nothing will be come out unless we stand on our own legs, fight together, nothing will come out by mere expression of our emotions.

Now, the Deputy Minister belongs to the Backward Classes and the State Minister, Prof. Nurul Hasan, belongs to a minority community. They feel the actual spirit of the provision. Can they do something against the officials with bureaucreatic mentality? You know better. This Government had to appoint a Parliamentary Committee and you were also lucky enough to be there for some time. You were also there when we examined the State Government Secretaries and the head of departments and sometimes the Chief Ministers. But, when the matter came up for promotion and amelioration, then all sorts of difficulties have been expressed.

Now, coming to the report of action taken, yesterday a long time has been taken on this action taken issue. The Parliamentary Committee was consti-

tuted in December 1968 and it examined the report very exhaustively with the help of officials. We thought that nothing will be done because the Commissioner has been stripped of all his powers as if birds cannot fly when their wings have been clipped or a man cannot walk when his legs are chopped off. So is the case with the Commissioner for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes You know it very well that the Commissioner was assisted by 17 Assistant Commissioners representing every State. But in 1957 these posts were abolished and 5 zonal directors were appointed in those States. The functions of these Directors are not known to the States. I know very well the heart of the people and the many leaders. They go by the advice of the officials Then they forgot So is the case with our Dr. Karan Singh. He is listening to me, so I am referring to him. I wrote a letter to him. Just now my friend mentioned about his Civil Aviation Department.

16.54 hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

I wrote to him for a small job of Asstt. Traffic Officer. I wrote to the Secretary and I met the Secretary personally but they disqualified the boy who was a high Second Class MA. He was not found fit for the job of Asstt. Traffic Officer in spite of his high qualifications He is at present working as a professor in a College. I know Dr. Karan Singh very well, personally also. He has all sympathy for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes but his officials stand in the way. So, is the case with so many officers. What can Prof. Nurul Hasan do? I have been repeatedly telling here in this House that this gigantic task should be entrusted to the Home Minister. Why? We suggested in our report, the report of the Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes that either it should be with the Home Ministry or with the Prime Minister. Why? Because we examined and found that everything has to come from the Ministry of Home Affairs. From that point of view, this portfolio should be either with the Home Ministry or with the Prime Minister. Who is the Home Minister now? It is the Prime Minister who is the Home Minister. We have requested the Prime Minister. At the same time, I feel personally, it is a matter of influence, over the State Governments and the Ministry. If the Prime Minister personally writes or sends a word, then the State Government whether of the DMK or of the Congress or any other party, takes the matter seriously and will try to do something. Otherwise it is just a cry in the wilderness.

One hon. Member from Mizoram stated about this. You have heard his speech. What is the percentage of literacy there? It is 55 per cent in Mizoram. What is the percentage for the whole of India? It is 34 per cent I think. What is the percentage of Kerala which is the highest? It is 62 per cent. What is the percentage of our Deputy Minister's State? It is 64 per cent. Therefore this question arises If you go to the figure of the IAS and IPS services in Assam, you will find that out of 100, 70 are from the hills, that is, scheduled tribes. Not even Brahmins or caste Hindus could compete with them; this is because the Christian Missionaries have been imparting education in those areas from British days. Here sometimes we scold and speak ill of Cristian Missionaries. But the great service which they have done should not be forgotten.

Yesterday Dr. Karan Singh was also present when Mother Teresa spoke about the services of Christian Missionaries in India. She said that only by love you can do service to the humanity. Where is the love in

[Shri D. Basumatari]

our Minister's heart? We are talking about untouchability. What is untouchability? Is untouchability practised with Babuji? There is no untouchability practised with you also, Mr. Chairman. It is only education which is needed. It is only education by which you can solve the problem of untouchability.

I don't say that Government has not taken this question into consideration seriously. They have appointed various Committees and commissions after Commissions have been appointed; which have submitted their reports; their reports remained where they were, they were not implemented. This is the position. Mr Verrier Elwin submitted a report on tribal blocks. There were 489 tribal blocks which were constituted in the areas where there were predominently tribal population. I visited those areas in 1961 with the Dhebarbhai Commission and I found the tribals wealthy, healthy and with sufficient lands. The Parliamentary Committee on the Welfare of Schedule Castes and Scheduled Tribes also visited those areas when we found that their lands were taken away by the non-tribals and they were now without lands Roads have been constructed. Schools after schools have been opened. But if you enquire about the children belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, you will find, there are not more than one per cent or two per cent, We found in Kerala also some tribal areas.

17 hrs.

We saw buildings after buildings; they were very nice buildings too. And there were so many guest-houses also. I thought personally that things had improved, because when I had visited that area long before in 1960, I had found it a jungle, and we could not go and penetrate that area; But now not only roads are there, but even tar roads are there. But when we visited the tribal area, what did we find? We found women with their hair in coils. We found men without any food. And in the schools we found cattle and cow-dung. We visited some schools and some colleges also. For the tribal area, there is a tribal college. The name is very nice. But when we asked how many of the boys and girls were tribals and Scheduled Castes, the answer was that it was only 2 per cent. and in some places it was only 1 per cent This is the plight of the tribals and Scheduled Castes. We do not grudge non-tribals being educated; we do not grudge Brahmins and caste-Hindus getting education there. But at least some justice should be done After all the money is being allocated for imparting education to the tribals and Scheduled Castes So, why should non-tribal people take advantage of this? Of course, they did try to show us some boys and girls and said that they were tribal boys and girls But when we asked their fathers and mothers, out of fear they could not say anything to us frankly, but when we took them some distance away from them and asked them, they confessed that they were caste-Hindus and they were not tribals or Scheduled Castes. So, I would like to point that in the name of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, these things are happening there.

As regards literacy, the percentage of literacy for the whole of India is 34 But really speaking, the percentage of literacy for tribals is only 8. In the case of Mizoram, it is 55 per cent, in the case of Khasi Hills, it is 64 per cent and in the Garo Hills, it is 40 per cent Taking the whole tribal population together, the average percentage works out to 8 per cent. This is all became of the Christian Missionaries who imparted education in tribal areas of Assam. But what

about Scheduled Castes? After all, the Scheduled Castes are not living in jungles. They are not all living in the villages. They are mostly in the cities. Why is it that untouchability is still practised there and why are these atrocities being committed in the cities?

My hon. friend who preceded me was talking about the position in his State and was saying that the tribals and Scheduled Castes were separated in the hostels and they were treated as untouchables. If that be the case, then may I ask him why he is blindly supporting the DMK Government? Why should he support a Government which cannot ameliorate the conditions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Of course, he may ask me what I am doing. I may tell him that I am fighting in my State I am fighting there for my existence; I am fighting for.....

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharapuram). That system of separate mess and separate hostel does not exist in Tamil Nadu.

SHRI R. P ULAGANAMBI: There are no separate hostels or messes in Tamil Nadu.

SHRI D. BASUMATARI: While we blame the State Government and we are fighting with the State Government, we do so within our State; we are blaming the activities of the Congress Government in Assam, and we are fighting with them, but we do so in Assam itself and not here at the Centre.

SHRI K. S. CHAVDA: About 42 Harijans were burnt alive in one clash in Tamil Nadu.

SHRI R. P. ULAGANAMBI: A case had been filed in that regard, and the offenders were punished, and they are now in jail.

SHRI D. BASUMATARI: My hon. friend has rightly reminded me of the clash which took place at Kilavenmani in Tamil Nadu in which about 45 Harijan boys and girls were burnt alive. We had met the Chief Minister Mr. M. Karunanidhi, and he had himself admitted that he was sorry for the incident. Let us stand together and work together and fight with Government. Mr. Chairman, you also belong to the Scheduled Castes and are an elder member. I would request you to plead with the Prime Minister to see that this department is taken over under the Home Ministry in her portfolio. I do not say anything against our friends who are in charge of it now. But the thing is that you have to work through the State Governments. The State Governments are the instrument through which we have to work for the upliftment of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, this can best be done if this department is within the Home Ministry. Hence, I would request you also to use your good offices to persuade our Prime Minister so that she may take over this portfolio in the Home Ministry.

*SHRIMATI BHARGAVI THANKAPPAN (Adoor): Mr. Chairman, Sir, this year we are celebrating the silver jubilee of our Independence. The democratic form of government came into existence here 25 years back. In our Constitution it has been clearly stated that the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Backward Classes people should be protected. With that end in view we had set up many parliamentary committees and commissions in the past. These committees and commissions tried to assess the progress made by these people in the field of education and also in other fields. They found that the progress was very limited. That is why we sought to raise discussions here on these reports.

The progress of any society can be gauged by its position in the field of

*The original speech was delivered in Malyalam.

[Shrimati Bhargava Thankappan]

education and in the economic and cultural fields. In the case of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes we find that their progress is nil. In the industrial field these people are always living in backwardness Their lot could not be bettered by the Government so far. In the field of agriculture and industry and commerce even in spite of the fact that we got independence 25 years ago the statistics reveal that no progress has been made In the field of agriculture, from the figures available from 1901 to 1961, we find that these people have got only 2 2 percent But in the industrial and commercial field from 6 per cent in 1901 they have come down to 4 per cent in 1961, after 60 long years of development That means instead of making some progress their position is deteriorating If this is the pace at which they are going to make progress only God can help them

In respect of agriculture the present laws are not giving them adequate protection. Therefore, the Government should take some steps to change the present laws in order to give more protection to them Fallow and surplus lands should be taken over by the Government and distributed to the landless Harijans If this is not done, Sir, the land reforms that we propose to make will not yield the desired result. The Government should, therefore, pay more attention to safeguard the interest of these people. My humble request to the Government is that they should enact land reform laws that are beneficial to these people.

As I said earlier, in the field of industry and Commerce also they are backward. They do not get loans or grants from nationalised or commercial banks because the required provisions are not there in our laws. These laws should be amended and adequate provisions should be made to see that they are able to get grants and loans from the banks. Then only we will be able to bring about some progress among these people.

In the economic and social fields they are in utter backwardness. They are very backward in the social field. Their experiences tell many heartrending stories. Many such stories have been narrated by the hon. Members who spoke before me. The Harijans are being ill-treated by caste Hindus From the papers we find that recently in U.P. and also in Delhi which is the Capital of India and in some other parts of the country there were incidents of such ill-treatment of Harijans. In a village in Uttar Pradesh where about 150 families of Harijans lived, according to press reports, their mothers and sisters were molested by caste Hindus. It is very sad that even after 25 years of freedom we have not been able to bring about any change in the situation

In the field of education the amount of stipends and scholarships given to Harijan students is very small Considering the present cost of living this amount will not serve any purpose. My request to the Government is that the amount of stipends and scholarships should be increased More primary and secondary schools should be opened so that children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes could be accommodated and given free education Afterwards they should also be sent abroad for higher education by the Government.

Even though there is reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the matter of employment in Government service, there is no reservation for promotion and they are ignored. Therefore my request to the Government is that in the matter of promotion also there should be reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

What we have found is that the efforts of the commissions set up for

the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not bringing forward any fruitful effect towards the uplift of these people. I conclude, Sir, with the request that necessary legislation should be passed to see that these backward people are brought up to the level of our society and they are able to live a better standard of life.

SHRI K. S. CHAVDA (Patan): Mr. Chairman, Sir, the 19th report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the year 1969-70 is being discussed today, the 16th November, 1972. We have always pleaded that the report should be presented to and discussed in the House every year in time. The Minister concerned gives an assurance to the House that it will be done. While replying to the debate in the Lok Sabha in 1967, the then Minister of Social Welfare, Shri Asoka Mehta, assured the House that every year the report would be presented to the House at the time of the budget session But this assurance has not been implemented by the Government

In 1970, we discussed all the three reports, and while taking part in the discussion on these reports, Shri Morarji Desai said:

> "Is not the problem of human existence more important than anything else? Is not human dignity more important than anything else? That is what this problem is and that is why we must give it the highest priority."

The reports for 1970-71 and 1971-72 have not been laid on the Table of the House yet. What about the action taken on the recommendations made in 1969-70 report? Shri Asoka Mehta who replied in 1967 said:

> "It is not yet possible for the Government to say what steps were taken because the final steps are taken only after taking into account the discussion that takes place in this House as well as the other House.

Action on 1969-70 recommendations will be taken in 1973. Regarding action taken, he has given one important assurance:

> "Here again I should like to assure the House that a brief report on the steps taken by the Government on the various recommendations will be placed before November-December session of Parliament this year, as well as in the future"

This assurance has also not been fulfilled by the Government That is how this socialist Government headed by Shrimati Indira Gandhi behaves in the amelioration of the conditions of the SCST people. With what face could they say to the States to implement the safeguards under the Constitution? For this reason, once again I request the hon. Minister to give an assurance that the report would be presented every year at the time of the budget session and the Chair and the House should see that this report is discussed in time.

There is another point regarding the atrocities committed on the SCST people and the failure of the Government to curb them. Gruesome incidents of Harijans being burnt alive or murdered by the non-Scheduled Caste persons have been increasing year after year. According to the Home Minister's reply to a question 1,112 Harijans were murdered in the country during 1967, 68 and 69; these incidents have increased during the last three years. Many a time this House has discussed such cases but the Government has not taken any action to curb the increasing number of atrocities committed on the Harijans.

[Shri K. S. Chavda]

Government do not take care even to give correct information regarding the atrocities committed on the Harijans. For example, when I raised the question of a Harijan girl being burnt alive in Madhya Pradesh continuously for three sessions of the Rajya Sabha in 1970, though I was assured by the Prime Minister because she happens to be the Home Minister, that she would give correct information, no information had been given till now. I would ask: suppose a Muslim girl had been burnt alive by a caste Hindu, would the Prime Minister afford to remain silent? Hue and cry had been made when such incidents regarding Muslims—not burning of the girls alive but ill-treatment etc.—came before the House. When a Harijan girl had been burnt alive, no action was taken. Therefore, I suggest that a high-power commission should be appointed to find out the causes of increasing number of atrocities committed on the Harijans and to find out ways and means to curb such types of atrocities in the country.

My other point is regarding the failure of the Government to continue after 1968-69 the scheme of post-matric scholarships of the SCST students as a centrally sponsored scheme

This scheme was introduced by the Government of India in 1944. Since then the Government of India has been incurring expenditure on these post-matric scholarships. In 1968-69, Government spent Rs. 6.46 crores on this The National Development Council, headed by Shrimati Indira Gandhi, decided against the will of the Chief Ministers to impose this expenditure on the States. Since then this scheme has been transferred to the State sector, with the commencement of the fourth plan.

Government has provided Rs. 10.75 crores for *ex gratia* payment to the former rulers. But this Government which claims to be socialist does not provide even Rs. 6.46 crores for the post-matric scholarships of the scheduled caste and scheduled tribe students. These scholarships are awarded to the students who are poorest among the scheduled castes. There is a means-cum-merit test. These scholarships are given only to those students whose parents' or guardian's annual income from all sources does not exceed Rs. 3600. In his reply to a starred question on the 13th the Deputy Minister gave a wrong reply that the limit is Rs. 6000 It is not so

DR. KAILAS: It is Rs. 6,000, not Rs. 3,600. Please check it.

SHRI K. S CHAVDA: I have already checked it

A centrally sponsored scheme of reclamation of waste land and resettlement of landless agricultural labourers was introduced during the third plan. This scheme also has been transferred to the State sector I know that land being a State subject, every State Government has got its own scheme for distribution of cultivable land among the landless labourers With a view to supplement the State Governments' schemes, the Government of India introduced this scheme. Under this scheme upto the end of 1968, some 1 101 lakh families of landless agricultural labourers were resettled on about 2 lakh hectares of land. But this scheme has been transferred to the State sector.

Again, the Slum Clearance Scheme, which was started in 1956 as a Centrally sponsored scheme, also stands transferred to the State sector. The Central assistance is now given to the State Governments in the shape of block loan and block grants. They can spend them anyway they like. The States are reluctant and not in-

terested in spending money on the welfare of Scheduled Castes and Tribes. I would request that the Centrally sponsored schemes for Scheduled Castes and Tribes, which were transferred to the State sector, should be transferred back to the Centre as Centrally-sponsored schemes.

My fourth point is about increasing the rate of post-matric scholarships for Scheduled Castes and Tribes in accordance with the increased cost of living. The rates of post-matric scholarships were fixed nearly twenty years ago and since then there has been no increase in the rates, though there were persistent demands for the increase in the rates. In reply to my letter to Shri Asoka Mehta, the then Minister of Social Welfare, he wrote to me on 21st February 1969:

> "We have taken note of the general feeling that there should be a general increase in the rates for scholarships, and will strive to meet their wish, to the extent possible, from the next academic year."

The Elayaperumal Committee also recommended the linking of the scholarship rates with the cost of living. When the matter was further pressed in Parliament, the late Shri Govinda Menon informed the House on the 31st July 1969 that he was satisfied that the post-matric scholarships given particlarly to students in technical institutions were not sufficient. Therefore, he had raised the question of enhancing the quantum of post-matric scholarships and the matter was perding with the Finance Ministry. The proposal was there to enhance the scholarships to those who were undergoing technical courses by 100 per cent and 50 per cent in the case of academic courses. The matter was awaiting clearance from Finance. The Finance Ministry has not given clearance till now.

The Parliamentary Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Tribes took up this matter with the Ministry when the representative of the Department of Social Welfare stated.

> "We are proposing to increase its rate consistent with the cost of living index. This has remained static for a number of years. Proposals are now under consideration to increase them substantially."

Yesterday because of some circumstances I could not move my motion. I have covered those four points now and I would request the government to consider those four suggestions

श्री राम प्रताप सिंह (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आयुक्त के 19वें प्रतिवेदन पर यहां पर जो प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है उसपर अपने विचारों को प्रकट करने का अवसर दिया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित प्रतिवेदन पर विचार करते समय उनकी वर्तमान मनोदशा और उनकी वर्तमान भावना पर हमें विचार करना होगा। हमने उनकी भावना को बहुत नजदीक से समझने की कोशिश की है और हमने जो उनकी भावना पाई है उसको यहां पर व्यक्त करना चाहता हूं :

> जी में आता है सूरज, चांद तारे नोच, लूं,
> सैकड़ों शोषक अभी भी हैं नजर के सामने।

यह है उनके अर्धचेतन, अवचेतन मन की अवस्था। देश का इतिहास, समाजशास्त्र और धर्मशास्त्र इस बात का साक्षी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों

का उच्च जातियों ने और पूंजीपतियों ने उनका पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से युगों तक शोषण किया है। इसके साथ-साथ उनके ऊपर नाना प्रकार के अनाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार हुये हैं जो मानवता की सबसे बड़ी पराजय रही है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ने अपने रक्त से समाज की सदैव संरचना की। वे हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, परन्तु खेद का विषय है कि उनकी स्थिति इस समय भी अत्यन्त दयनीय है, कष्टदायक और चिन्ताजनक है। आज भी जो जीवन की आधारभूत आवश्यकतायें हैं—भोजन, वस्त्र तथा आवास, उनके लिये उनकी पूर्ति नहीं हो पाई। हमें अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना होगा। जहां एक ओर बड़े बड़े पूंजीपतियों के कुत्ते तक दूध पीना पसन्द नहीं करते वहां दूसरी ओर हमारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भूख के मारे कभी कभी घास की पत्तियों की रोटियां खानी पड़ती हैं, पेड़ों के पत्तों की रोटियां खानी पड़ती हैं। एक ओर जहां धनी वर्ग दिन में तीन-तीन बार टेरिकाट के कपड़े बदलता है वहां दूसरी ओर हमारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों को अपनी लज्जा को छिपाने के लिये वस्त्र तक नहीं मिलता। जहां एक ओर पूंजीपतियों के प्रासादों और अट्टालिकाओं में वासना का तांडव नृत्य होता है वहां दूसरी ओर जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां हैं उनकी झोंपड़ियों में जहां सूरज और चांद की किरणें नीचे आती हैं वहीं पानी की भी एक बूंद पड़ती है तो वह उनकी चारपाई पर आती है। ऐसी स्थिति में हमारे देश की अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां जिन झोंपड़ियों में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं वह उनकी जीवित समाधि बन गई हैं।

शिक्षा के अभाव में, जो सामाजिक कुरीतियां, उनके विश्वास उनकी परम्पराएं, उनकी मान्यतायें उनके रीति रिवाज हैं जिनको हम उनकी सभ्यता और संस्कृति कहते हैं, वह उनके प्रति घोर अन्याय है। हमारे देश की नारियां, हमारी बेटियां, बहनें और मातायें अभाव अथवा परम्परागत कारणों से अर्द्धनग्नावस्था में रहें, यह हमारे देश के लिये, हमारी उच्च कही जाने वाली भारतीय जातियों के लिये लज्जा की बात है। हमें उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाना होगा। उन्हें प्रत्येक दृष्टि से समाज में समानता का दर्जा दिलाना होगा तथा उनको आर्थिक और सामाजिक विषमताओं से मुक्त करना होगा।

मैं जनसंघ के नेता श्री जोशी का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ और अपनी भाषा के चमत्कार से जिस बात को कहने की कोशिश की कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनकी अपनी संस्कृति है और वह अपनी सांस्कृतिक विशेषता के कारण नग्नावस्था में रह रही हैं। उनका कुछ भी अभिप्राय हो, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनसंघ

[श्री च. प्रताप सिंह]

जी आज ऐसी पार्टी है जो देश में वर्ण व्यवस्था को रखना चाहती है। वह आज भी चाहती है कि अछूत को अछूत ही समझा जाये।

श्री राम रतन शर्मा (बांदा) : आप जनसंघ के लिए क्यों कह रहे हैं। इस बात पर सरकार को त्यागपत्र देना चाहिए कि उसने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं किया। आप दूसरों पर आरोप क्यों लगा रहे हैं?

श्री चं प्रताप सिंह : अब मैं दूसरी बात कहता हूं। खेद की बात है कि आज भी समाज की उच्च जातियों और अफसरों द्वारा उनसे बेगार ली जाती है। आज भी यद्यपि हमारे और उनके रक्त में कोई अन्तर नहीं है, हम दोनों धरती पर एक प्रकार से चलते हैं तो भी उनमें और हममें भेद समझा जाता है। आज भी हमारी आदिवासी लड़कियों की बिक्री होती है। आदिवासी और हरिजन लड़कियों के साथ शीलभंग की दुर्घटनायें होती हैं। उन्हें शारीरिक दण्ड दिये जाते हैं। खेद का विषय है कि आज जब हम अपनी स्वतंत्रता का रजत जयन्ती वर्ष मना रहे हैं, हरिजन भाइयों को जीवित जलाने की घटनायें होती हैं। कानून के होते हुए भी न तो उन्हें भूमि और रोजी मिल पाती है, न आवास और वस्त्र की व्यवस्था हो पाती है, न उनका जो नौकरियों में कोटा है वही उसको पूर्ण कर के हम दे पा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश की नौकरशाही जिम्मेदार है और उसको हमें ठीक करना होगा क्योंकि यह स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रति उच्च जातियों और अफसरों की जो मनोवृत्ति है उसमें परिवर्तन लाना होगा तभी सरकार द्वारा किये जाने वाले प्रयासों से उन्हें लाभ मिल पायेगा। जो देश के अफसर हैं उनके द्वारा हम उन्हें जो सहायता पहुंचाना चाहते हैं वह पहुंच नहीं पाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए जिन सुविधाओं का प्रावधान इस प्रतिवेदन में किया गया है वह आवश्यकता के अनुरूप नही है। युगो युगो तक जिनका शोषण हुआ है, युगो युगो तक जिनके जीवन के साथ मजाक हुआ है उन्हे 25 वर्ष से हम जितना दे पाये है वह आवश्यकता का केवल पाच प्रतिशत है। प्रतिवेदन में जो व्यवस्था की गई है यदि उतना भी हम उनको दे देते है तो मै समझता हू वह डूबते के लिए तिनके का सहारा हो सकता है।

हमारी दल की नेता श्रीमती इन्दिरा गाधी, जो प्रधान मत्री, भारत सरकार हैं, उन्हे सदैव ही हिन्दुस्तान की अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति रही है, पूर्ण सद्भावना रही है और उन्होने बराबर इस बात को चाहा है कि उनकी जो कठिनाइया है, उनकी जो समस्याये हैं उनका निराकरण होना चाहिए। साथ ही साथ हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदैव यह नीति रही है, सदैव उसका यह इतिहास रहा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी हुई जातियो तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियो के हितो की ओर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाये। हमें विश्वास है कि हमारे सामने जो प्रतिवेदन

[श्री रुद्र प्रताप सिंह]

प्रस्तुत किया गया है यद्यपि वह जैसा मैंने पहले कहा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं और आशाओं के अनुरूप नहीं है तो भी जितना प्रावधान किया गया है हम उस पर सख्ती के साथ और ईमानदारी के साथ अमल करेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आवश्यकताओं को देखते हुए अगर यह विभाग प्रधान मंत्री स्वयं अपने हाथ में ले लेतीं तो अच्छा होता।

अन्त में मैं आपकी आज्ञा से एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा :

रफीको आओ बदल दें निज़ामे आलम को
फरेबो मक्र के पर्दे को तार तार करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री धनशाह प्रधान (शहडोल) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की समस्या मूल रूप से निर्धन और दुर्बल वर्ग की समस्या है। अनुसूचित जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट शिक्षा, जागृति, भूमि आवंटन, कुटीर उद्योग, गृह-निर्माण सहायता, छुआछूत निवारण, सर पर मैला ढोने की प्रथा बन्द करने और नौकरियों में उनके स्थान सुरक्षित करने आदि विषयों का 448 पृष्ठों का प्रतिवेदन है।

इन समस्याओं को बुनियादी ढंग से हल करने के लिये सरकार को क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों पर, हमारे देश के गांवों और नगरों में रहने वाले इन छोटे छोटे लोगों पर जो अत्याचार होता है उस को माननीय सदस्यों ने बड़ी गम्भीरता के साथ आप के सामने रखा है। अपने क्षेत्र में तथा अन्य स्थानों पर भी हम लोग दौरा करके आए हैं। हमने उड़ीसा, कलकत्ता आदि का दौरा किया है। महाराष्ट्र और नागपुर में भी हम गए हैं। वहां पर आदिवासियों की संख्या 75 प्रतिशत है। लेकिन वहां उनको विशेष मान्यता नहीं मिली हुई है। बौद्धों को मान्यता मिली हुई जब कि उन में से बीस प्रतिशत बौद्ध होंगे। मैं चाहता हूं कि बौद्धों के साथ साथ इनको भी मान्यता प्रदान की जाए। आज देश से गरीबी हटाने का नारा दिया जाता है और इस नारे को देने वाली सरकार की हालत यह है कि सुदूर गांवों में सफाई कर्मचारियों की निकृष्ट स्थिति की ओर इसका ध्यान ही नहीं जाता है। यह कितना विरोधाभास है। इसको एक विडम्बना ही कहा जाएगा। यह एक कलंक हमारे माथे पर है। आज भी सफाई कर्मचारियों की स्थिति और उनकी आर्थिक दशा हृदयविदारक है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। शहरों में रहने वाले तथा कथित सभ्य समाज को उनकी वास्तविक स्थिति की झलक भी नहीं मिल पाती है।

17.40 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चल कर भगवान बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, जब संसार के प्रति विरक्त रहने लगे तो उनके पिता ने यह आज्ञा दी कि सिद्धार्थ के लिए

इतनी अधिक सुविधायें जुटा दी जाएं कि उन्हें निर्धनता, बीमारी और मृत्यु की झलक तक पाने का अवसर न मिले यही दशा आज के समाज की है । वातानुकूलित और सजे सजाए कमरो मे रहने वाले समाजवादी मंत्री क्या कभी इन लोगो की झलक पा सकेंगे ? मै समझता हू कि वह निर्धन वर्ग की कल्पना भी नही कर सकते ।

अनुसूचित जातियो की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है । यह देश मे प्रति व्यक्ति की आय की समस्या है । गरीबी और अमीरी के बीच की खाई कम करने का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है । इस पर आपको अविलम्ब ध्यान देना चाहिये ।

हरिजनो के बच्चे स्कूल मे जाने मे सकोच करते है । उन्हे भरती भी नही किया जाता है । अभी अभी मेरे क्षेत्र मे जो कुछ हुआ है, उसको मै आपको बतलाना चाहता हू । यह समाचार नवभारत मे, जो जबलपुर मे प्रकाशित होता है उस मे छपा है । आठ आदिवासियो पर गिन गिन कर 72-72 कोडे बरसाए गए है और उन पर एक एक हजार रुपया जुर्माना किया गया है । उनका अपराध केवल मात्र यह था वे एक वन विभाग के अन्तर्गत जगली रास्ते मे निकल गए थे । जंगल विभाग के कर्मचारियो ने अन्य विभागो के कर्मचारियो से सहयोग कर उन से भिड कर उन पर अत्याचार किए ।

आदिवासी लडकियों के बेचे जाने की घटनाए तथा उनको लज्जित किये जाने की घटनाएं आपके सामने आ गई है । उनकी बिक्री और हत्या की घटनाओं का यहां वर्णन किया जा चुका है । यह कितनी लज्जा की बात है कि आजादी के पच्चीस वर्ष बाद भी भारत के नारी वर्ग का अपमान हो रहा है । ससार के विभिन्न देशों मे भारत की महिलाओ को जाने से रोकने मे सरकार असफल रही है । यह सारे देश के लिए अपमान की बात है । केन्द्रीय सरकार को इस विषय मे सख्त कदम उठाना चाहिये और इस सदन को इस बात का पक्का विश्वास दिलाना चाहिये कि भविष्य मे ऐसा कभी नही होगा ।

मेरा एक सुझाव है । जहां पर विशेष जाति के लोग रहते हो वहा पर यह देखा गया है कि उसी जाति का उम्मीदवार खडा होता है । इससे जातपात को बढावा मिलता है और जातपात के आधार पर चुनाव जीता भी जाता है । इसके बारे में भी सरकार को उपाय करना चाहिये और देखना चाहिये कि जातपात की भावना को बढावा न मिले ।

सरकार कहती है कि वह कई प्रकार की सुविधाये आदिवासियो और हरिजनो को दे रही है और आगे और भी देने जा रही है । लेकिन मैं आपको बताऊ कि कुछ दिन पहले एक आदिवासी श्री महादेव बैगा ग्राम गिजरी, पो० बिरसिंह पुर पाली जिला शहडोल, की जमीन मेरे इलाके मे चौराहे पर खडे हो कर आठ हजार मे नीलाम कर दी गई है । वह 42 एकड़ जमीन थी । उनको चार हजार रुपया जमा करवाना था । वह 3,650 जमा करवा चुका है । शेष जमा नहीं करा सका । उसने समय मांगा

[श्री बनशाह प्रधान]

उसकी जमीन को जो 42 एकड़ थी सरे आम नीलाम कर दिया गया और वह बेचारा एक किनारे खड़ा रो रहा था जबकि बड़े अन्य लोग बोली लगा रहे थे। उसकी भूमि को नीलाम कर दिया गया। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं इनकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये। और मैं कुछ सुझाव भी आपको देना चाहता हूं। अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना बनाई जाए। इस में उनकी अधिक से अधिक मदद की जाए।

सामाजिक समता लाने के लिए कदम उठाएं जाएं और उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रभावशाली उपाय किए जाएं।

उनके द्वारा बोली जाने वाली मातृ भाषा और बोलियों को शिक्षा का माध्यम बनाने की योजना बनाई जाए। अदालतों या तहसीलों से जो उनको नोटिस आदि आते हैं वे उनको उनकी भाषा में लिख कर दिए जाएं ताकि वे उनको समझ सकें और उनका जवाब दे सकें।

जनजातियों से गैर जनजातियों को भूमि बेचने, गिरवी रखने अथवा स्थानान्तरण करने को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं।

अनुसूचित जाति और आदिम जाति के आयुक्त के संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनः चालू किया जाए। ऐसा यदि किया जाए तो उनकी समस्याओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा सकेगा।

आदिवासी नीति निर्धारण आयोग अध्यक्ष इस सदन के एक माननीय सदस्य हैं। वह इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि आदिवासी नीति निर्धारण के बारे में जो भी आपका निर्णय हो उसको आप दो तीन दिन में प्रस्तुत कर दें।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीबों के साथ जो अन्याय होता है चाहे वह कहीं भी हो उसकी आप रोकथाम करें और उनको राहत दिलाने की कृपा करें।

SHRI B. V. NAIK (Kanara): The report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was submitted to the President of India on 26th June 1971. This was furnished to us on the 22nd December, 1971. Yesterday there was some considerable amount of commotion that the follow-up or the action-taken report has not been placed yet, along with this report for the year 1969-70. It would be most appropriate if we lay our fingers here upon whom we call the constitutional officers. The Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is responsible under the Constitution just like the Auditor General and Comptroller or the Attorney-General, to the President of India.

Under the circumstances, I could not understand for a minute as to how the Ministry of Social Welfare (which also did not labour to defend itself) could be asked to give this action-taken report. In the case of such constitutional officers like the Auditor-General, they are directly responsible to the President of India. It is for the Commissioner to present the action-taken report and it is to this Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that the State Governments are also responsible.

SHRI R. D. BHANDARE: Who listens to him?

SHRI B. V. NAIK: Why should anyone listen to anybody else? I am listening to you. Who listens to the Auditor-General? This is a very valid point, who listens to anybody? That is exactly what N. K. Bose....

SHRI SHAMBHU NATH (Saidpur): So far as the Attorney-General is concerned, he has been given all executive and administrative powers. But so far as the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned, he is powerless. Who listens to him? You can see the report of the Elayaperumal Committee, you can see the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes presented to the House This has been demanded by him at various times. But who listens to him?

SHRI B. V NAIK: May we go into the Constitutional argument at a later stage? I could answer you, but I don't want to be diverted. Powers are enumerated to every body who functions under the Constitution. He is equivalent to everyone else Under the circumstances

SHRI SHAMBHU NATH: It is well and good if it is so

SHRI B V NAIK: Under the circumstances, the hon Member, I think would appreciate that it is for this particular constitutional officer to exercise power and bring to book those which are errand States. Herein, I do come into a very sensitive point. Now that many things have been said even by some Members of the Opposition who have been the greatest advocates of the autonomy of the States and who have seen the disadvantages whenever a sort of political crisis develops as to what happens to the autonomy of the State, I would, as a Member of this House, not like to cast unnecessarily aspersions against this State or that State, linguistic or otherwise. I would not like to cast aspersions on this Minister or that Minister or this Chief Minister or that Chief Minister. I would like to ask the Minister who is responsible for answering this House what he has been doing about these States. If they have not been able to comply, it is none of my business. I must unfortunately mention here that there has been a convention that they will ask that we must be able to get along with our Chief Minister. I submit that the Chief Minister is not responsible to me; he is not sitting here. The Ministers of the State do not sit here. We are directly concerned, as people directly elected from the parliamentary constituencies with our own Ministers dealing with the specific subjects. If the Central Ministry feels that there is some lacuna in handling adequately these linguistic States in our country, it is most appropriate for them to come forward with appropriate legislation in order to rectify these lacunae or these administrative handicaps that exist in our government in the country today. I would like to close up that topic there and go back to the very valid points which this great Gandhian scholar, Mr. Nakul Bose has made in his report. Though the report is for the year 1969-70, it is of substantial topical interest. In this report, I would like to draw attention to something to which we shall have to pay greater attention in the years to come.

There have been attempts in our country to interpret what we have called as Scheduled Castes in the Constitution in such a way that we have somehow equated them with the concept of untouchables in the Indian society. There are people who give a Marxian angle to this and call this as a sort of class *versus* caste system. There are others who try in this social equalisation process to describe it as our hon. friend from the DMK said as something which is worse than even the treatment of the blacks in America. Well, I would like to submit that absolutely there is no question of racial discrimination. The entire Indian society, irrespective of castes and

[SHRI B. V. NAIK]

creeds and religious is absolutely one. Nobody doubts about it, and the Harijans and the Brahmins or the Christians or the Muslims, everyone of them, come from the same—bloodstock. In these circumstances, to borrow from the Americanism of the West or something about the Negro problem in the USA and try a hotch-potch to apply it in our country would, I would say, be a travesty of truth and a travesty of even simple commonsense.

On the question of economic equalisation in this country, there is a debate and there has been a debate and this debate will go on. When it is a question of bringing about a parity between the haves and the have-nots, when it is a question of growth *versus* social justice, how far our industrial or agricultural production will take off and in the process of equalisation, what the pitfalls will be and so on can be a matter of a substantial amount of debate. In respect of social equalisation, in respect of treating a fellow human being as a fellow human being, in respect of treating all the castes, creeds and communities as equal, there is no investment involved. There is no budget allotment involved. There is no expenditure involved. It is not a monetary problem. It is a simple question of refashioning our thoughts and then evolving an egalitarian society.

In this connection, I would like to ask our friends, particularly this section of society, as to why they should be imitative, why at all they should crave to gain entry into the temples Why should they at all try to be imitative of the hierarchical Hindu order of society and try to gain entry into Hindu temples or try to touch somebody who is considered to be untouchable?

Here I would say that there is also a system which I would call regional disparity in respect of untouchability. There are some portions of our country which have criminally neglected in equalising this section of our society. In this respect, I am proud of the fact that I come from a part of western India where some of the ghastly stories that have been told about some other parts of the country—I do not want to name them—are not a truism, are not there. I am proud of it. We are going about with social equalisation there.

In respect of economic equalisation, I would like to make a very valid point. The report of the Commissioner says in paras 1.57 and 1.58 very categorically that when it comes to the question of redistribution of land, in order to see that this land is made into a productive unit, there should also be a flow. When we distribute the surplus land after the imposition of ceilings, we should be in a position to give at least the minimum holding I would like the hon Minister to make a categorical statement on this point

The Government of Mysore have appointed a Backward Classes Commission They have requested for the inclusion of Lambanis among the Scheduled Tribes who are not yet so included in certain areas of the State Even in the district of North Kanara, there is a tribe by name Halaki Vokkals. These people have gone back in the time-scale in the course of the last 25 years. Their case to be included in the Scheduled Tribes should also be considered most sympathetically.

There has been considerable criticism that we have not done enough In the hierarchical Hindu order of society which has been in existence for the last 5,000 years, I wonder whether 25 years are anythng more than a second in an hour. Under the circumstances, given the time, we are quite confident that this anachronistic system can be abolished, and it will be abolished, before long.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri K. Marak. This is his maiden speech.

SHRI K. MARAK (Tura): Mr. Deputy-Speaker, Sir, at the very outset, I have to introduce myself as one coming from a backward area or district of the country, that is, the Garo Hills in the infant State of Meghalaya, and also belonging to one of the most backward of the hill tribes.

I am now on my legs not only to beg for sufficient financial assistance but mainly to beg for real understanding, sympathy and sacrifice of the rest of the country.

18 hrs.

Our leaders in the past had passed a Quit India Resolution against the powerful British Government, well equipped with men and materials, with grim determination and with the full and clear knowledge of the consequences. They had implemented their Resolution fully and drove out the British from India. Our present leaders can also pass a Quit Our Hearts Resolution against selfishness which includes, of course, in sincerity and dishonesty, and with the some determination, understanding and sacrifice. Otherwise, the policy or slogan to bring all people of the country to the same level—

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue tomorrow.

18.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, November 17, 1972/Kartika 26, 1894 (Saka).

GIPND—L—2417LS—20-12-72—.010.